भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3875

शुक्रवार, 27 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में पीएलआई के अंतर्गत संवितरित प्रोत्साहन राशि

3875. श्री कपिल सिब्बलः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2025-26 से अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के अंतर्गत संवितरित किए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2025 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार इन क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण की क्षमता में वृद्धि हुई है; और

(ग) आर्थिक सर्वेक्षण, 2025 में उल्लेखित आपूर्ति श्रृंखला संबंधी कमियों को दूर करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): सरकार ने देश में घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने, निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार का सृजन करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें लागू की हैं। 31 दिसंबर, 2025 तक, स्कीमों ने 2.16 लाख करोड़ रुपए से अधिक का संचयी निवेश आकर्षित किया है, 20.41 लाख करोड़ रुपए से अधिक का संचयी उत्पादन/बिक्री सृजित की है और 8.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात किया है, जबकि 14 क्षेत्रों में 14.39 लाख से अधिक व्यक्तियों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) के लिए रोजगार का सृजन किया है।

i. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र (व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रानिक विनिर्माण और आईटी हार्डवेयर 2.0) के तहत लगभग 15,554 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन संवितरित किए गए हैं।

ii. ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक क्षेत्र के अंतर्गत, लगभग 2377.56 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन संवितरित किए गए हैं।

(ख): इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण क्षमताः

i. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र (व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रानिक विनिर्माण और आईटी हार्डवेयर 2.0) के तहत, इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर 2025 तक 59 कंपनियों द्वारा लगभग 2,45,375 करोड़ रुपए का वृद्धिशील उत्पादन दर्ज किया गया है।

ii. ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक क्षेत्र के तहत, इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर 2025 तक 72 कंपनियों द्वारा लगभग 13,126 करोड़ रुपए का वृद्धिशील उत्पादन दर्ज किया गया है।

iii. कुल मिलाकर पीएलआई स्कीमों ने 2.16 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित किया है। इसने इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर 2025 तक लगभग 4,20,581 करोड़ रुपए का वृद्धिशील उत्पादन किया है। अपनी शुरुआत के बाद से, इन स्कीमों के कारण 14 क्षेत्रों में 20.41 लाख करोड़ रुपए से अधिक का संचयी उत्पादन/बिक्री हुई है।

(ग): घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने, आयात निर्भरता को कम करने और देश में आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही पीएलआई स्कीमों के अलावा, सरकार ने निम्नलिखित पहलें की हैंः

i. सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम का कार्यान्वयन जिसका उद्देश्य घरेलू सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करना, अत्यधिक केंद्रित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आयात पर निर्भरता को कम करना है;

ii. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण स्कीम (ईसीएमएस), एसपीईसीएस, ईएमसी और एम-एसआईपीएस, जो इलेक्ट्रॉनिक घटकों के घरेलू विनिर्माण और क्लस्टर आधारित ईकोसिस्टम के निर्माण को बढ़ावा देती हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होती है;

iii. पीएम गति शक्ति-जो समन्वित अवसंरचना आयोजना और मल्टीमोडल कनेक्टिविटी को सक्षम बनाता है, लॉजिस्टिक्स लागत और परिवहन के समय को कम करता है तथा आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार करता है;

iv. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जो प्रक्रिया ईष्टतमीकरण, डिजिटलीकरण और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी पर केंद्रित है, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाओं की विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है;

v. वैश्विक आरईपीएम बाजार में एक प्रमुख भागीदार के रूप में भारत की आत्मनिर्भरता और स्थिति को बढ़ाने के लिए सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने की स्कीम।

vi. राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन घरेलू और विदेशी स्रोतों से खनिज उपलब्धता सुनिश्चित करके भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करता है।

*****